63. Bharatiya Mahilaya Vikas Sangh, at Bajipur Road, P.O. Rs Barh, Distt. Patna.

64. Bihar Gramin Seva Parishad, Patna.

Statement-II

Details of tfie N.G.Os. in Bihar Which have been blacklisted by other Organisations and adopted by Capart since 1990

1. Champaram Sevashram, Village, Dumri Baiju, P.O. Badka Balua, Distt. East Champaran.
2. Vaishali Vikas Parishad, At/P.O. Rasulpur, Distt. Muzaffarpur.
3. Mayasthali (Bhagwanpur) Sudanand Bhawan, Distt. Muzaffarpur.
4. Shri Jagannath Bal Vikas kendra, At Purad Tola, Distt. Muzaffarpur.
5. Zila Gramin Vikas Sangh, Indira Gandhi, Sri Krishna Sevashram Sansthan, At & P.O. Akhadaghat, Muzaffarpur.

बंजर भूमि

4716. श्री जनेश्वर मिश्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोंजगार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि देश में एक लाख एकड़ भूमि प्रत्येक वर्ष बंजर हो जाती हैं;

(ख)यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग)सरकार द्वारा इस भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और राजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) और (ख) बजंरभूमि सहित समस्याग्रस्त भूमि की विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रफल के बारे में वैज्ञानिक रूप से वार्षिकक आधार पर कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, अत: प्रत्येक वर्ष बंजर भूमि में परिवर्तित होने वाली भूमि के बारे में सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय **शूर** संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के 1995 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह सूचित किया गया है कि देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्र 6.25 मिलियन हैक्टेयर हैं। भूमि कटाव और भूमि के अवक्रमण की प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अवक्रमित और बंजर हो जाती हैं, कई कारणों से घटित होती है जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों का असफल रहना, भू-संसाधनों का कम उपयोग किया जाना, उपयुक्त जल तथा भूमि प्रबंधन के अभाव की वजह से भूमि की गुणवत्ता में कमी आना तथा प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी कारण आदि।

(ग)इस समय बंजरभूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की समस्याग्रस्त भूमि को विकसित करने/पुन: उपजाऊ बनाने से संबंधित संघटक शामिल हैं जिनके तहत भूमि को अवक्रमित होने से रोका जाता है ओर ऐसी भूमि को सतत रूप से उत्पादन कारी उपयोग में लाया जाता हैं:-

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

(क)समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(ख)प्रौद्योगिक विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना

(ग)निवेश संवर्धन योजना

(घ)स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान योजना

(ड.)बंजरभूमि विकास कृतिक बल

(च)सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

(छ)मरूभूमि विकास कार्यक्रम

2.**कृषि मंत्रालय**

(क)नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ संभावना वाली नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

(ख)क्षारीय भूमि को पुन: उपजाऊ बनाना

(ग)वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना

(घ)ड्राम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास परियोजना

3. **जल संसाधन मंत्रालय**

(क)कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

4. पर्यावरण और वन मंत्रालय

(क)समेकित वनरोपण तथा परिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम

(ख)क्षेत्रोन्मुखी जलाऊ लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम

(ग)वनरोपण और वृक्षरोपण के लिए सहायता अनुदान योजना

(घ)परिस्थतिकी कृतिक बल योजना

Development of Gautam Buddha Network to Promote Tourism

4717. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have taken fresh initiatives to formulate a com prehensive plan of action for develop ment of Gautam Buddha Network (places of historical importance) in the country to promote tourism;

(b) if so, the details thereof alongwith the fund provided and utilised during the Eighth plan period alongwith achievements;

(c) the details of international tourists visiting these places each year for the past three years, year-wise and foreign exchange earned; and

(d) the details of foreign aid received utilised so far for development of tourists spots Buddha Network and assistance in the pipeline alongwith details of action plan for the current year?

THE MINISTER FOR PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM (SHRI MAD AN LAL KHURANA): (a) and (b) a Task Force appointed by the Government to identify the centres associated with the life of Buddha submitted its report in October 1986. The report identified Sarnath, Kushinagar, Pipraha-wa, Sravasti and Sankasia in U.P. and Patna, Bodhgaya, Nalanda, Rajgir and Vaishali in Bihar for development. Based on the report, the development of these centres was taken up with the loan assistance of Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan. The amount spent on this project during the 8th Plan was Rs. 125 crores;

The second Task Force set up in June 1987 identified the Buddhist Centres in other states for development by the respective States. Based on the project proposal received from the Maharashtra Govt. OECF loan assistance was provided for the Conservation and Development of Ajanta-Ellora. The u.nount spent on this project during the 8th Plan was Rs. 41.48 crores.

(c) The statistics of international tourists visiting these individual places and the foreign exchange earning from them are not available.

(d) The OECF loan assistance is not available in advance. The implementing agencies i.e. the State Governments have to spend the money first and them claim reimbursement from OECF. For the development of infrastructural facilities along identified Budhhist travel circuits in Uttar Pradesh and Bihar Rs. 155 crores has been reimbursed by OECF so far and for Ajanta-Ellora Conservation and tourism development project OECF reimbursed Rs. 54.14 crores so far.

Export of Hanidcrafts

4718. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the target set for export of handicrafts sector during 1997-98 and achievements made;

(b) whether it is a fact that the share of Southern and Eastern regions in the total experts of handicrafts from the country was only eight per cent.

(c) if so, the details thereof alongwith steps proposed to be taken for correcting regional imbalance in export of Indian handicrafts; and

(d) the steps taken or proposed to be taken for giving a boost to some important lesser known crafts in the interna-